

हवा-पानी की शुद्धता-संरक्षण की जवाबदेही

राजधानी दिल्ली व एनसीआर में अनियंत्रित वायु प्रदूषण को लेकर देश की शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार का वुलिस को फिर फटकार लगायी है। कोर्ट ने नागरिकों जातायी कि वायु गुणवत्ता की बेहद अंभी स्थिति होने पर सुधार हेतु ग्रैप-4 लागू करने में कोताही बरती जा रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार का वुलिस को आड़े हाथों लिया कि क्यों रोक के बावजूद दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश जरी है। कोर्ट ने दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश की निगरानी को तेरह बकीलों को नियुक्त किया, जो सोमवार को अपनी रिपोर्ट देंगे। कोर्ट ने दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हमियांगा व उत्तर प्रदेश सरकारों को सख्ती से ग्रैप-4 की व्यवस्था लागू करने को कहा। अदालत का कहना था कि सभी राज्यों का दायित्व है कि नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए। दरअसल, न्यायमूर्ति अंगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ग्रैप-4 व्यवस्था लागू करने की खामियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बात पर विद्वास नहीं किया जा सकता है कि दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है। अदालत ने केंद्र सरकार से दिल्ली में प्रवेश के 113 स्थानों पर निगरानी के लिये वुलिस कर्मियों की तैयारी को कहा, इसमें प्रवेश के तेरह मार्ग ट्रॉकों के लिये हैं। दरअसल, अदालत ने दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले गञ्ज हमियांगा तथा उत्तर प्रदेश सरकारों को 18 नवंबर को निर्देश दिया था कि ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंधों के क्रियान्वयन के लिये तुरंट टीम गठित की जाए। कोर्ट ने सख्ती से पार्वतियां लागू न किये जाने पर नाराजगी जाती। उल्लेखनीय है कि इस समाह की शुरुआत में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्स्प्रूआई के गंभीर से अधिक के स्तर पर पहुंचने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-4 लागू किया गया था। जिसके अंतर्गत ट्रॉकों व भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश व सार्वजनिक निर्माण पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी।

प्रश्न है कि क्यों हमारी सरकार जन-स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में तब तक सोची रही है, जब तक कि पानी सिर के ऊपर से न जुरझने लगे। क्यों हर साल शीर्ष अदालत को सरकार, पुलिस व पर्यावरण संरक्षण हेतु बनी संस्थाओं को नींद से जगाना पड़ता है? क्यों अदालत पहले अदाले दे और फिर उपरके क्रियान्वयन की निगरानी करे? क्यों सरकारें आग लगाने पर कुंआ खोदने की फिरतर से बाज नहीं आती। अदालत ने कहा कि हर नागरिक को स्वच्छ हवा देना सरकारों का दायित्व है तो क्या सरकारें जिम्मेदारी निभा रही है? सदी की दस्तक देते ही हर साल अंतर्राष्ट्रीय नवंबर में प्रदूषण संकट पैदा होता है, फिर भी सारे साल प्रदूषण को काबू करने के उपया क्यों नहीं किए कि जाते? क्यों प्रदूषण संकट गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद सरकारें हाथ-पैर मारना शुरू करती हैं? कल्पन कीजिए श्वसनतंत्र व दमा जैसे रोगों से ग्रस्त लोग इस भयावह प्रदूषण संकट से कैसे जूँझ रहे होंगे? बिंदबाना ही कि हम आने वाली पीढ़ियों के पीछे परिवेश-पर्यावरण छोड़ेंगे। सवाल हवा का ही नहीं, पानी पर भी बड़ा संकट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने नासा व जर्मनी के उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर चिंता बढ़ाने वाला खुलासा किया कि वर्ष 2014 के बाद से स्वच्छ जल के स्तर पर अन्तर्यांशित गिरावट देखी गई है। निश्चित रूप से इस स्थिति के लिये हम सब सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। पानी के अंधाधुंध उत्थान, बन क्षेत्रफल का संकुचन और इंसान की अंतहीन लिप्साओं व जीलों को भी प्रदूषित कर दिया है। यह इंसान के लिये जगने का बक्तव्य है।



श्री अमित शाह

क्रैंप्री गृह एवं बनाती है।

सहकारिता मंत्री

सहकारिता बिभाग

पूँजी वाले लोगों को समृद्ध

बनाने के लिये एक बहुत बड़ा साधन है।

हमारे देश में सहकारिता की एक विस्तृत

परंपरा तो रही है, लेकिन आजार्दी से पहले

सहकारिता जिस प्रकार अर्थात् आंदोलन

का माध्यम बनी, उसे और भी अधिक ऊँचा

और शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व

में यह परिवर्तन लाया गया है।

हमारे देश में सहकारिता की एक विस्तृत

परंपरा तो रही है, लेकिन आजार्दी से पहले

सहकारिता को समृद्धि देने के लिये तुरंट

कार्यक्रम लाने की ज़रूरत है।

अब भारत का सहकारिता आंदोलन एक

सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है, जो समाज में अर्थिक रूप से आकांक्षी लोगों को न सिर्फ़ समृद्धि बनानी जैसे उद्देश्य तुरंट

अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा

रिहायिसिक पल का साक्षी बनने जा रहा है।

देश 25-30 नवंबर, 2024 को दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गर्भांधन (आईसीए) महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबाजी करने को वित्त देता है। आईसीए के 130 वर्ष के इतिहास में यह पहली मोका है, जब भारत में अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा

रिहायिसिक पल का साक्षी बनने जा रहा है।

देश 25-30 नवंबर, 2024 को दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गर्भांधन (आईसीए) महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबाजी करने को वित्त देता है। आईसीए के 130 वर्ष के इतिहास में यह पहली मोका है, जब भारत में अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा

रिहायिसिक पल का साक्षी बनने जा रहा है।

देश 25-30 नवंबर, 2024 को दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गर्भांधन (आईसीए) महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबाजी करने को वित्त देता है। आईसीए के 130 वर्ष के इतिहास में यह पहली मोका है, जब भारत में अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा

रिहायिसिक पल का साक्षी बनने जा रहा है।

देश 25-30 नवंबर, 2024 को दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गर्भांधन (आईसीए) महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबाजी करने को वित्त देता है। आईसीए के 130 वर्ष के इतिहास में यह पहली मोका है, जब भारत में अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा

रिहायिसिक पल का साक्षी बनने जा रहा है।

देश 25-30 नवंबर, 2024 को दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गर्भांधन (आईसीए) महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबाजी करने को वित्त देता है। आईसीए के 130 वर्ष के इतिहास में यह पहली मोका है, जब भारत में अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा

रिहायिसिक पल का साक्षी बनने जा रहा है।

देश 25-30 नवंबर, 2024 को दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गर्भांधन (आईसीए) महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबाजी करने को वित्त देता है। आईसीए के 130 वर्ष के इतिहास में यह पहली मोका है, जब भारत में अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा

रिहायिसिक पल का साक्षी बनने जा रहा है।

देश 25-30 नवंबर, 2024 को दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गर्भांधन (आईसीए) महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबाजी करने को वित्त देता है। आईसीए के 130 वर्ष के इतिहास में यह पहली मोका है, जब भारत में अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा

रिहायिसिक पल का साक्षी बनने जा रहा है।

देश 25-30 नवंबर, 2024 को दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गर्भांधन (आईसीए) महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबाजी करने को वित्त देता है। आईसीए के 130 वर्ष के इतिहास में यह पहली मोका है, जब भारत में अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा

रिहायिसिक पल का साक्षी बनने जा रहा है।

देश 25-30 नवंबर, 2024 को दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गर्भांधन (आईसीए) महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबाजी करने को वित्त देता है। आईसीए के 130 वर्ष के इतिहास में यह पहली मोका है, जब भारत में अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा

रिहायिसिक पल का साक्षी बनने जा रहा है।

देश 25-30 नवंबर, 2024 को दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गर्भांधन (आईसीए) महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबाजी करने को वित्त देता है। आईसीए के 130 वर्ष के इतिहास में यह पहली मोका है, जब भारत में अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा

रिहायिसिक पल का साक्षी बनने जा रहा है।

देश 25-30 नवंबर, 2024 को दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गर्भांधन (आईसीए) महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबाजी करने को वित्त देता है। आईसीए के 130 वर्ष के इतिहास में यह प

